गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 131
दि. 10.09.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

नई जीएसटी दरें : कृषि क्षेत्र और किसानों की समृद्धि के लिए वरदान

नई जीएसटी दरें कृषि और डेयरी क्षेत्र बड़े बदलाव का संकेत है। जीएसटी दरों में कटौती से देशभर के किसान, कृषि व डेयरी क्षेत्र के कामगार, पशुपालक बेहद प्रसन्न हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नई दरों को क्रांतिकारी फैसला बताते हुए ऐतिहासिक बदलाव की उम्मीद जताई है। जीएसटी रिफॉर्म का प्रभाव छोटे और मंझौले किसानों के बीच व्यापक रूप से देखा जा सकेगा।

राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे, उम्मीद से अधिककुल 452 वोट मिले, मिल रहीं बधाईयां

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। इस जीत के साथ, 68 वर्षीय राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। उन्हें कुल 452 वोट मिले, जो उम्मीद से अधिक थे।

इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट के साथ हार का सामना करना पड़ा। उपराष्ट्रपति का यह पद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए में शामिल पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए, शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई देते हुए लिखा, "सी. पी. राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई! सार्वजनिक जीवन में आपके दशकों के समृद्ध अनुभव राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आपको एक सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देती हूं।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, "सी.पी. राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे।"

गृह मंत्री अमित शाह ने सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राधाकृष्णन की समझदारी और प्रशासनिक ज्ञान भारतीय संसदीय लोकतंत्र को और बेहतर बनाने में मदद करेगा, खासकर हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा के लिए।

शाह ने कहा, " सी.पी. राधाकृष्णन जी को भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि जमीनी स्तर से उठे एक नेता के रूप में आपकी समझदारी और प्रशासन के बारे में गहरा ज्ञान हमारी संसदीय लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ लाने में मदद करेगा, ताकि हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा की जा सके। मैं आपको उच्च सदन की पवित्रता के संरक्षक के रूप में आपकी यात्रा के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सी.पी. राधाकृष्णन ने अपने बधाई संदेश में लिखा, " सी.पी. राधाकृष्णन जी को भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई।

सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति का चुनाव की जीत पर खुशी जताई

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन के चुने जाने के बाद उन्हें बधाई दी है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया मंगलवार को दिन में पूरी की गई। शाम को वोटों की गिनती के बाद एनडीए कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट जारी होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही प्रदेश के अन्य सीनियर भाजपा नेताओं ने विजयी उम्मीदवार को बधाई दी।

सीएम योगी ने क्या कहा?

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर विजयी एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को हार्दिक बधाई। राष्ट्र के प्रति आपकी अटूट निष्ठा, दृढ़ प्रतिबद्धता और समृद्ध अनुभव भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सशक्त एवं उज्ज्वल बनाएगा।

श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुबई में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में ऐतिहासिक यूपीआई-यूपीयू एकीकरण का शुभारंभ किया

भारत ने वैश्विक डाक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई: श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपीयू कांग्रेस, दुबई

सिंधिया ने ग्लोबल पोस्टल समिट में दो प्रमुख यूपीयू परिषदों के लिए भारत की दावेदारी की घोषणा की

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई-यूपीयू एकीकरण परियोजना का अनावरण किया। यह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सीमा पार प्रेषण में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया,

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए

डाक विभाग (डीओपी), एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) द्वारा विकसित यह पहल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म (आईपी) के साथ एकीकृत करती है। इससे डाक नेटवर्क की पहुंच यूपीआई की गति और सामर्थ्य के साथ जुड़ जाती है।

श्री सिंधिया ने इसे "एक तकनीकी लॉन्च से कहीं बढ़कर, एक सामाजिक समझौता" बताया। उन्होंने कहा, "डाक नेटवर्क की विश्वसनीयता और यूपीआई की गति का मतलब है कि सीमा पार के परिवार तेजी से, सुरक्षित और बहुत कम लागत पर पैसा भेज सकते हैं। यह इस बात की पुष्टि करता है कि नागरिकों के लिए बनाए गए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सीमाओं के पार जोड़कर मानवता की बेहतर सेवा की जा सकती है।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने मेडागास्कर की मंत्री के साथ सिविल सेवा प्रशिक्षण और शासन सुधारों पर द्विपक्षीय वार्ता की

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मेडागास्कर की श्रम, रोजगार और लोक सेवा मंत्री श्रीमती हनीत्रा फिटियावाना रजाकबोआना के बीच भारत की शासन पद्धतियों और पारदर्शिता एवं दक्षता में प्रौद्योगिकी के उपयोग से हुई सुधारों को मेडागास्कर के लोक सेवकों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित बैठक हुई।

आदि-कर्मयोगी अभियान के एक हिस्से के रूप में प्रतिष्ठित जनजातीय लोगों के एक समूह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की

(जीएनएस)।

विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध पृष्ठभूमि के प्रतिष्ठित जनजातीय लोगों के एक समूह ने आज (9 सितंबर, 2025) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। जनजातीय कार्य मंत्रालय के 'आदि कर्मयोगी अभियान' के तहत राष्ट्रपति भवन में इस समूह का आगमन हुआ। इस पहल के तहत राष्ट्रपति भवन में जनजातीय नेताओं की ऐसी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। इस चरण की इस श्रृंखला में यह अंतिम बैठक थी।

उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय समाज और देश के भविष्य को आकार देने की दिशा में संवाद और सहयोग का एक अनोखा प्रयास है। यह पहल एक समावेशी और समतामूलक भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि जनजातीय समुदाय न केवल विकास के लाभार्थी बनें, बल्कि राष्ट्र के भविष्य के सह-निमार्ता भी बनें।

राष्ट्रपति ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान उत्तरदायी शासन के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने की एक परिवर्तनकारी पहल है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष जुलाई में इस अभियान के शुभारंभ के बाद से, एक लाख गांवों में, अधिकारियों, स्वयंसेवकों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और जनजातीय युवाओं सहित 20 लाख आदि-कर्मयोगियों को प्रेरित किया जा रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि एक लाख आदि सेवा केंद्रों की पहचान एकल खिड़की सेवा और शिकायत निवारण केंद्रों के रूप में की गई है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों को आवश्यक बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान कर रहा है। वन अधिकार अधिनियम सामाजिक न्याय, समानता और पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक सशक्तिकरण केवल योजनाओं से नहीं आता है।

बल्कि, सच्चा सशक्तिकरण लोगों के अधिकारों की मान्यता से आकार लेता है। यह उन अधिकारों के सम्मान से मजबूत होता है और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधित्व से कायम रहता है। उन्होंने आदिवासी समुदायों के सदस्यों से अपनी विकास यात्रा की सक्रिय जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें विभिन्न मंचों पर अपने विचार व्यक्त करने और व्यवस्थाओं को जवाबदेह बनाने की सलाह दी।

राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी को मिलकर, अपने आदिवासी भाइयों और बहनों की सक्रिय भागीदारी के साथ, एक ऐसे समाज और देश के निर्माण के लिए काम करना चाहिए जहां समानता, न्याय और सम्मान का वातावरण हो, जहां आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराएं संरक्षित हों, और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के अधिकारों की रक्षा हो। उन्होंने आदिवासी लोगों की विशिष्ट पहचान और समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करते हुए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में बादल फटने, बारिश और भूस्खलन के कारण बाढ़ की स्थिति और नुकसान की समीक्षा के लिए 9 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के चंबा, भरमौर, कांगड़ा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक की जिसमें राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन भी किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया व गुरदासपुर में बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और नुकसान आकलन किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 सितंबर 2025 को पंजाब का दौरा किया और पंजाब के प्रभावित इलाकों में बादल फटने और भारी बारिश से आई बाढ़ की स्थिति और उससे हुए नुकसान की समीक्षा की।

प्रधानमंत्री ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद, उन्होंने गुरदासपुर में अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक आधिकारिक समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की और पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन भी किया।

प्रधानमंत्री ने राज्य आपदा राहत कोष में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की सहायता के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें पीएम आवास योजना के अंतर्गत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, पीएमएनआरएफ के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे।

कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। जिन बोरवेल में गाद भर गई है या जो बह गए हैं, उनके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार के विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत परियोजना आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।

11वें गोला-बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बजरे, एलएसएएम 25 (यार्ड 135) का प्रक्षेपण

(जीएनएस)।

11वें गोला-बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बजरे, एलएसएएम 25 (यार्ड 135) के प्रक्षेपण समारोह का

08 सितंबर 2025 को मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे में आयोजन किया गया। प्रक्षेपण समारोह के मुख्य अतिथि रियर एडमिरल विशाल बिश्नोई, एसीडब्ल्यूपीएंडए थे।

11वें गोला-बारूद-सह-टारपीडो-सह-मिसाइल बजरे के निर्माण का अनुबंध एमएसएमई शिपयार्ड, मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे के साथ 05 मार्च 21 को संपन्न हुआ। इन बजरों को शिपयार्ड द्वारा क्रमशः एक भारतीय पोत डिजाइन फर्म और भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। समुद्री कौशल के लिए इस मॉडल का परीक्षण नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल) विशाखापत्तनम में किया गया था। शिपयार्ड ने अब तक ग्यारह में से दस बजरे सफलतापूर्वक वितरित किए हैं और भारतीय नौसेना द्वारा अपने परिचालन विकास के लिए इनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

ये बजरे भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं।

सरस आजीविका मेले का केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह व मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूती देने के साथ ही स्वदेशी अपनाने का प्रण लेते हुए वृहद सरस आजीविका मेले का औपचारिक शुभारंभ आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित यह सरस आजीविका मेला मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, दिल्ली में 5 सितंबर से लगाया गया है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। मेले में 400 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों की लखपति दीदियों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।

सम्पादकीय

प्रचण्ड विरोध प्रदर्शन ने गिराई ओली सरकार

नेपाल में काफी दिन पहले से बड़े पैमाने पर पनप रहे विरोध प्रदर्शनों का ही परिणाम है कि वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ा तथा जो त्याग पत्र देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए उन्हें प्रदर्शनकारियों के हाथों पिटना पड़ा। देश की सत्ता सेना ने संभाल ली और सोशल मीडिया ऐप बहाल कर शांति स्थापित करने के लिए युवकों से अपील की है। प्रदर्शन का स्वरूप सोमवार को अत्याधिक उग्रा हुआ तो पुलिस ने फायरिग करके 20 लोगों को मार डाला। आंदोलन का सामान्य कारण तो यही बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाए जाने से जेन जी यानि 1997-2012 तक के जन्में युवा और विद्याथा नाराज हो गए। दरअसल दिख तो रहा है कि मात्र दो दिन के प्रचण्ड विरोध प्रदर्शन में नेपाल की सरकार गिर गईं किन्तु वास्तविकता यह है कि इस पर्वतीय देश में सरकार के खिलाफ हर वर्ग आवाज उठाता रहा है। इसका एक ही कारण है कि नेपाल में कम्युनिस्ट नेताओं के हाथ में ही सत्ता घूम फिर कर रही और वे आवंठ भ्रष्टाचार में डूब गए। पूर्व महाराजा ज्ञानेन्द्र के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करके देशवासियों ने इस बात का एहसास करा दिया कि ओली सरकार न सिर्प भ्रष्ट है बल्कि निकम्मी और निठल्ली भी है। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि उन्हें दोबारा राजशाही चाहिए। अभी मार्च 2025 में ही तो ह्यहमी नेपालह्न नाम की एनजीओ बनी थी जिसके कर्ताधर्ता सूदन गुरूंग हैं। राज परिवार के निकटवता संबंधी काठमांडु के मेयर बालेन्द्र शाह ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। ये दोनों ही राजशाही और हिन्दुत्व के समर्थक माने जाते हैं। यदि नेपाल की जनता लोकतंत्र को छोड़कर राजशाही की मांग कर रही है तो निाति तौर पर इसका अर्थ यह नहीं है कि लोकतंत्र से अच्छा राजतंत्र है। इसका तो सीधा और सरल मतलब यही है कि जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपी गईं वे नागरिकों के प्रति अपने राजधर्म को निभाने में असफल रहे। तभी नागरिकों के लिए निष्ठुरता और लापरवाही करते रहे। अटकलें लगाईं जा रही हैं कि नेपाल में जो वुछ भी हुआ, उसके पहले यह श्रीलंका, बांग्लादेश में हो चुका है। अटकलें यह भी लगाईं जा रही है कि ओली एससीओ यानि शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने चीन गए थे और वहां वह राष्ट्रपति शी जिनपिग से भी मिले थे। फिर उन्होंने चीन के बाद भारत यात्रा की भी योजना बनाई थी। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने ओली के खिलाफ कोईं षडांत्र करके वहां की सरकार गिरा दी। अटकलों का आधार देखने में तो सही लगता है किन्तु जरूरी नहीं कि वह सत्य हो। किन्तु इस बात से इंकार तो नहीं किया जा सकता कि नेपाल में अमेरिकी हितों के खिलाफ और चीन के हितों के लिए ओली सरकार ने लगातार पैसले किए। 42000 करोड़ डालर का निवेश अमेरिकी है नेपाल में लेकिन ऐप बन्द किया गया अमेरिका का, जबकि चीन के ऐप पर कोईं पाबंदी नहीं लगाईं गईं। इसलिए यदि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल में ओली सरकार को उखाड़ पेंकने में अमेरिका शामिल है तो इसे पूरी तरह नाकार भी नहीं जा सकता। अपना तो मानना है कि ओली के पतन का कारण खुद ओली ही हैं। उन्होंने झूठ और फरेब का ऐसा लबादा ओढ़ रखा था जो उन्हें सौम्य, संवेदनशील एवं राष्ट्रभक्त राजनेता की तरह प्रदर्शित तो करता था किन्तु वह चरित्र से षडांत्रकारी और स्वाथा व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ आधारहीन माहौल बनाकर संसद में उत्तराखंड राज्य की लिपुलेख यानि भारतीय जमीन को अपना बताने के लिए प्रस्ताव पारित करा लिया। लेकिन फिर भी भारत ने नेपाल के प्रति किसी भी तरह न तो कड़ी प्रतिव्रिया दी और न ही उसको प्रतिवर्ष दिए जाने वाले अनुदान में कटौती की। आज नेपाल की जनता सब वुछ समझती है। वह डपरोशंख नहीं है। उसे सब वुछ पता है कि ओली ने अपने स्वार्थ के लिए नेपाल के आंशिक इस्लामीकरण के लिए खाड़ी देशों से भारी भरकम रिश्वत ले ली है। ओली चीन से भी तमाम व्यक्तिगत लाभ ले चुके हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में क्रांति, कैसे नई पीढ़ी ने बदली दक्षिण एशिया की राजनीति ?

नेपाल इस समय भारी राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। शुरूआती दौर में यह मामला केवल युवाओं की सोशल मीडिया तक सीमित नाराजगी माना जा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे यह आंदोलन एक बड़े जनआंदोलन का रूप ले चुका है। शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुए प्रदर्शनों ने हिंसक रुख ले लिया और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा।

दरअसल, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर नए नियम थोपते हुए इसे "राष्ट्रीय हित की रक्षा" का कदम बताया। सरकार का दावा था कि इन प्लेटफॉर्म्स से राजस्व और नियंत्रण प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना।

देखते ही देखते इस आंदोलन की आंच टिक-टॉक (जो बैन नहीं था) पर वीडियो और हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इन वीडियोज ने नेताओं के बच्चों की ऐशो-आराम भरी जिंदगी और आम युवाओं की कठिनाइयों के बीच अंतर को उजागर किया।

भ्रष्टाचार और "नेपो किड्स" के खिलाफ ञ्जल्ल` का आक्रोश

युवाओं का गुस्सा सोशल मीडिया से आगे बढ़कर था। जिसमें भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ ञ्जल्ल` ने खुल कर सड़कों पर उतरें। हाल ही में नेपाल एयरलाइंस द्वारा विमानों की खरीद में सामने आए भ्रष्टाचार की रिपोर्ट ने आग में घी का काम किया। इसके साथ ही भारत के साथ नेपाल के बिगड़ते रिश्ते भी वहां की जनता के हक में नहीं थे। वहीं नेपाल का चीन के साथ लगाव बढ़ता जा रहा था जिससे नेपाली नागरिक सरकार से खफा थे।

9 सितंबर 2025 को काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ टायर जलाए और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस की सख़्ती में कई प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्षी नेताओं के घरों पर भी हमला किया। यहां तक कि कभी माओवादी आंदोलन का चेहरा रहे पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' के घर पर भी हमला हुआ।

दक्षिण एशिया में युवाओं के आंदोलन ने बदली तस्वीर

दक्षिण एशिया के कई देशों में हाल के सालों में युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों ने सत्ता के ढांचे को हिला कर रख दिया है। चाहे बात बांग्लादेश की हो या श्रीलंका की, नई पीढ़ी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कुप्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरकर बड़ा बदलाव ला दिया।

बांग्लादेशः शेख हसीना को छोड़ना पड़ा देश

बांग्लादेश में जुलाई 2024 में छात्रों और युवाओं ने सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को मिलने वाले विवादित कोटे के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन धीरे-धीरे भ्रष्टाचार और सत्ता में परिवारवाद के खिलाफ बड़े जनांदोलन में बदल गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा।

देश में अंतरिम व्यवस्था के लिए सेना और बिखरे हुए युवा नेतृत्व ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का

मुख्य सलाहकार बनाया। इस दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा की भी खबरें आईं, लेकिन मुख्य मुद्दे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और युवाओं की हताशा ही रहे।

श्रीलंका में 'गो होम गोटा' आंदोलन की शुरूआत और फिर हुआ सत्ता परिवर्तन

हमने देखा कैसे पड़ोसी देश श्रीलंका में 2022 में युवाओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया। देश में आर्थिक कुप्रबंधन ने हालात को इतना खराब कर दिया कि खाने-पीने की चीजों और ईंधन की भारी कमी हो गई। रोजाना बिजली कटौती और महंगाई ने जनता का गुस्सा भड़का दिया।

प्रदर्शन का नेतृत्व नई पीढ़ी ने किया, जो किसी पारंपरिक राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी थी। आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि तत्कालीन राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और उनके परिवार को सत्ता छोड़नी पड़ी। सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन #GoHomeGota जैसे हैशटैग ने पूरी दुनिया में आंदोलन को आवाज दे दी।

श्रीलंका में 2024 में हुए चुनावों में लेफ्ट गठबंधन के नेता अनुरा कुमारा डिसानायके ने सत्ता संभाली। चुनाव परिणामों में यह साफ दिखा कि युवाओं का आक्रोश अब संसद तक पहुंच चुका है। संसद में रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं और पहली बार चुने गए सांसद पहुंचे।

क्या है नेपाल का राजनीतिक भविष्य?

कई मीडिया रिपोर्टस की मानें तो नेपाल में आंदोलनकारियों का दावा है कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। वे इसे पूरी तरह गैर-राजनीतिक आंदोलन बता रहे हैं। यही कारण है कि भविष्य की राह और भी जटिल हो सकती है। भारत ने नेपाल में हुई हिंसा और मौतों की निंदा की है

केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्रभूमि शहर मान्यता समारोह 2025 के तहत शहरों को पुरस्कार प्रदान किए

पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु उपलब्धियों के लिए 11 सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले एनसीएपी शहरों को सम्मानित किया

एनसीएपी पुरस्कार 2025 के तहत वायु गुणवत्ता में इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत देश में अग्रणी

आर्द्रभूमि शहर मान्यता : इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई

130 भारतीय शहरों में स्वच्छ वायु और हरित बुनियादी ढांचे के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाए गए

प्रधानमंत्री के विजन ने शहरों को प्रेरित कियाः राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने 103 शहरी केंद्रों में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित कियाः श्री भूपेंद्र यादव

स्वच्छ वायु सर्वेक्षणः व्यापक प्रभाव के लिए वार्षिक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का वार्ड स्तर तक विस्तार किया जाएगा

देश भर में शहरी वायु गुणवत्ता पहलों का मार्गदर्शन करने के लिए सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का संग्रह जारी किया गया

केंद्रीय मंत्री ने प्रत्येक नागरिक के लिए सतत विकास और स्वच्छ वायु के मिशन को दोहराया

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की उपस्थिति में आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (ईएफएंडसीसी) द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और वेटलैंड शहर मान्यता समारोह 2025 का आयोजन किया गया। ईएफएंडसीसी ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 130 शहरों में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले शहरों को पुरस्कृत किया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक शक्तिशाली संदेश के साथ शुरू हुआ। प्रधानमंत्री

ने एकीकृत और आधुनिक दृष्टिकोण के माध्यम से मिशन मोड में प्रदूषण को कम करने के लिए 100 शहरों में कदम उठाने की अपील की।

श्री यादव द्वारा की गई अपील के अनुसार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का क्रियान्वयन कर रहा है, जो योजना निर्माण से वास्तविक कार्रवाई की ओर अग्रसर है और इसके परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अंतर्गत 130 एनसीएपी शहरों में से ग्यारह सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले शहरों को स्वच्छ वायु के मिशन को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और नवोन्मेषण का प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एक कठिन, बहु-स्तरीय मूल्यांकन तंत्र के रूप में संरचित है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत यथोचित परिश्रम पर आधारित है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एनसीएपी के तहत 130 शहरों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके।

निम्नलिखित शहरों को ईएफएंडसीसी मंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गएः

श्रेणी-1 (10 लाख से अधिक जनसंख्या):

इंदौर ने 200 में से 200 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1.5 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इंदौर ने पिछले वर्ष 16 लाख से अधिक पौधे लगाए, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। यहां सार्वजनिक परिवहन के लिए 120 इलेक्ट्रिक बसें और 150 सीएनजी बसें उपलब्ध हैं।

जबलपुर ने 200 में से 199 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। 1 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। जबलपुर ने 11 मेगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है और हरियाली विकसित की है।

आगरा और सूरत ने 200 में से 196 अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रत्येक शहर को 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया है। आगरा ने पुराने कचरा डंप स्थलों का सुधार किया है और मियावाकी वृक्षारोपण किया है। सूरत ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और कर लाभ प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है और 38 प्रतिशत

उपराष्ट्रपति चुनाव में इण्डिया गठबंधन को लगा तगड़ा झटका, जमकर हुई क्रॉस वोटिंग, राजग को मिले उम्मीद से अधिक वोट

एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी और इंडिया गठबंधन के बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया है।एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन को 452 वोट मिले वहीं दूसरी ओर, विपक्षी उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही हासिल हुए।

इस जीत के साथ, एनडीए ने लगभग दो-तिहाई बहुमत हासिल किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन को बड़ा झटका लगा है क्योंकि इस चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है।

सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने दावा किया कि 14 सांसदों ने क्रॉस-वोटिंग की, जिससे एनडीए को अतिरिक्त लाभ मिला। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन संख्या बल में वे एनडीए से पीछे रह गए। इस चुनाव में जीत के लिए 392 वोटों की आवश्यकता थी, जिसे राधाकृष्णन ने आसानी से हासिल कर लिया।

मंगलवार को हुए चुनाव में कुल 767 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें से 15 वोट अमान्य घोषित किए गए। कुल 782 सांसदों को मतदान का

अधिकार था। विपक्षी दलों से मिले 14 वोटों को एनडीए के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, खासकर तब जब 15 वोट अमान्य हो गए।

एनडीए के पास अपने सांसदों के अलावा क्रॉस-वोटिंग का भी लाभ रहा। एनडीए की कुल संख्या 427 थी, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों के जुड़ने से यह 438 हो गई। इसके अतिरिक्त, 14 अतिरिक्त वोट क्रॉस-वोटिंग के जरिए सीपी राधाकृष्णन के खाते में आए।

यह चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जुलाई में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद आयोजित किया गया था। संसद परिसर के वसुंधरा भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चला, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसदों ने भाग लिया।

विपक्ष ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा था, ताकि एक मजबूत संदेश दिया जा सके। हालांकि, एनडीए ने अपनी रणनीति के तहत क्रॉस-वोटिंग के माध्यम से विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाई और 452 वोट हासिल किए।

सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की थी, जिसका परिणाम कुछ क्रॉस-वोटिंग के रूप में सामने आया और एनडीए को लाभ मिला।

इस चुनाव में 15 वोट अमान्य पाए गए, जो कुल वोटों का लगभग 2 प्रतिशत है। इससे साफ है कि सांसदों ने मतदान प्रक्रिया में या तो गलतियाँ कीं या जानबूझकर इनवैलिड वोट डाले। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसे चुनावों में अमान्य वोटों की संख्या कम करने के लिए सांसदों को उचित मतदान प्रक्रिया का व्यापक प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

जीएसटी अगली पीढ़ी के सुधार मांग बढ़ाएंगे, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, रोजगार के अवसर सृजित करेंगे और इलेक्ट्रॉनिकी पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ बेहतर समेकन करेंगे

डिजिटल विकास और सस्ती आईसीटी हार्डवेयर उपलब्ध कराने के लिए एयर कंडीशनर, टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और पावर बैंक पर कम जीएसटी दर

(जीएनएस)।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में हाल ही में किए गए अगली पीढ़ी के सुधारों से इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत आने वाले क्षेत्रों, खासतौर पर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और आईसीटी हार्डवेयर (कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, स्विच, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्मार्टफोन और अन्य सभी संबंधित उपकरण) को बढ़ावा मिलेगा। दरों में कटौती से लोगों को सस्ती दर पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिलेंगे, साथ ही घरेलू विनिर्माण को मजबूती मिलेगी, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम और स्टार्ट-अप्स को समर्थन मिलेगा, जिससे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा

एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन (एलसीडी और एलईडी) जैसी उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किये जाने से सस्ती दर पर वस्तु उपलब्ध होने से घरेलू मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे कंप्रेसर, डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर जैसे घटकों में मजबूत बैकवर्ड लिंकेज (उद्योग को अपने उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध) बनने की संभावना है, और प्लास्टिक, वायरिंग, कूलिंग सिस्टम, एलईडी पैनल और असेंबली सेवाओं से जुड़े एमएसएमई के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। ये सुधार स्थानीय विनिर्माण को भी बढ़ावा देंगे, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। डिशवॉशर पर जीएसटी में कटौती से घरेलू जीवन स्तर भी बेहतर होगा।

डिजिटल विकास और सस्ते आईसीटी हार्डवेयर की उपलब्धता

मॉनिटर और प्रोजेक्टर (गैर-टीवी) पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों और डिजिटल शिक्षण केंद्रों की व्यय लागत कम होगी। सस्ते आईसीटी हार्डवेयर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक संचायकों (गैर-लिथियम-आयन, पावर बैंक सहित) पर जीएसटी 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने से ऊर्जा भंडारण समाधान सस्ती दर पर उपलब्ध होंगे, डिजिटल उपकरणों के लिए बैकअप पावर में सुधार आएगा और घरों और कार्यस्थलों पर ऊर्जा कुशल प्रणालियों को अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

जीएसटी में कमी से आंतरिक सुरक्षा संचार ढांचा भी सुदृढ़ होगा। दो-तरफा रेडियो (वॉकी-टॉकी) पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, जिससे पुलिस, अर्धसैनिक बलों और रक्षा बलों की खरीद लागत कम आएगी।

नवीकरणीय ऊर्जा और संवहनीयता को बढ़ावा

नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और सौर फोटोवोल्टिक सेलों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, जिससे घरेलू और औद्योगिक, दोनों स्तरों पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। कम्पोस्टिंग मशीनों पर भी अब 12 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिससे अपशिष्ट से ऊर्जा समाधानों और कम्पोस्टिंग तकनीकों को प्रोत्साहन मिलेगा और संधारणीय तथा स्मार्ट शहरों के निर्माण की परिकल्पना सुगमता से आगे बढ़ेगी।

जीएसटी सुधारों से भारत के इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलने की संभावना है। मांग को बढ़ावा मिलने तथा लागत मूल्य में कमी से घरेलू विनिर्माण तथा एमएसएमई के लिए अवसर उत्पन्न होंगे और रोजगार सृजन होगा। इससे स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत का समेकन और गहरा होगा।

भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस खेल के हैं बादशाह, कॉलेज में बने थे चैंपियन

(जीएनएस)।

एनडीए के सीनियर बीजेपी लीडर सीपी राधाकृष्णन ने 9 सितंबर 2025 को हुए चुनाव में शानदार जीत दर्ज की और देश के माननीय उपराष्ट्रपति बने। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। एनडीए उम्मीदवार और पूर्व राज्यपाल राधाकृष्णन को कुल 452 प्रथम वरीयता वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिल पाए। लगभग 96% सांसदों ने इस चुनाव में मतदान किया।

रह चुके हैं टेबल टेनिस के चैंपियन

राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने से न सिर्फ एनडीए की ताकत और मजबूत हुई है बल्कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव को भी देश की नई दिशा मानकर देखा जा रहा है। वे इससे पहले चार राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और दो बार कोयंबटूर से सांसद भी चुने गए। राजनीति और प्रशासन में अनुभव रखने वाले राधाकृष्णन का व्यक्तित्व सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। कॉलेज के दिनों में वे टेबल टेनिस के चैंपियन भी रहे हैं। खेलों के प्रति उनकी रुचि और मेहनत ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई।

सीपी राधाकृष्णन ने कहां से की है पढ़ाई

राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी स्थित वी.ओ. चिदंबरम कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई की। इसी दौरान उन्होंने कॉलेज स्तर की टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। यह जीत उनके शुरूआती सार्वजनिक उपलब्धियों में से एक थी, जिसने उन्हें सहपाठियों और शिक्षकों के बीच अलग पहचान दिलाई। टेबल टेनिस के अलावा वे लंबी दूरी की दौड़ में भी अच्छे धावक रहे। उनकी फिटनेस और सहनशक्ति उन्हें ट्रैक एंड फील्ड में खास बनाती थी।

क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना भी था पसंद

इसके अलावा उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना भी पसंद था। यानी खेलों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा साफ झलकती थी। सीपी राधाकृष्णन ने पढ़ाई और राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी खास मुकाम हासिल किया। बता दें कि इससे पहले राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। इतना ही नहीं वह झारखंड के भी गवर्नर रह चुके हैं।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग और आईआईएम कलकत्ता ने ऐतिहासिक डिजिटल गवर्नेंस और डेटा प्रबंधन प्रशिक्षण के तीसरे समूह के साथ ही सरकारी अधिकारियों को सशक्त बनाया

(जीएनएस)।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमइआईटीवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता (आईआईएमसी) के साथ साझेदारी करते हुए, 'डिजिटल शासन और डेटा प्रबंधन' पर प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे बैच का सफलतापूर्वक समापन किया। यह कार्यक्रम 8 से 10 सितंबर 2025 तक आईआईएम कलकत्ता परिसर में आयोजित किया जा रहा है।

पहले दो सत्रों की शानदार कामयाबी के बाद, इस तीसरे सत्र में देश भर के 28 वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए, जिनमें नई दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और पश्चिम बंगाल के केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।

यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, क्षमता निर्माण योजना का एक अहम हिस्सा है। यह 2.5-दिवसीय गहन और विशेष तरीके से तैयार किया गया कार्यक्रम, भारत के वरिष्ठ नौकरशाही को देश के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने और प्रभावी शासन के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करने हेतु जरुरी रणनीतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है।

पाठ्यक्रम के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल हैंः

- उन्नत डेटा गवर्नेंसः राष्ट्रीय डिजिटल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए रूपरेखाएँ और अत्याधुनिक अभ्यास।
- साइबर सुरक्षा और गोपनीयताः डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिक गोपनीयता की रक्षा के लिए मजबूत उपायों का कार्यान्वयन।
- डेटा-संचालित फैसले लेनाः कुशल नीति निर्माण और संगठनात्मक बदलावों के लिए विश्लेषण का लाभ उठाना।
- डिजिटल नेतृत्वः नागरिक-केंद्रित ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और लागू करने की रणनीतियाँ।

यह पाठ्यक्रम खासकर सरकारी प्रशासकों के सामने आने वाली मौजूदा चुनौतियों का हल निकालने के लिए तैयार किया गया है। इन वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता और तजुर्बा, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए सीखने के अनुभव को और गहरा बनाती है।

इस क्षमता-निर्माण योजना का मकसद सरकार के भीतर एक व्यापक डिजिटल व्यवस्था का निर्माण करना है, ताकि सभी को उच्च-गुणवत्ता, सरल और नागरिक-केंद्रित सेवाएँ दी जा सकें।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

रेल कर्मचारी की पुत्री पूजा कुमारी कॉम्बैट कुश्ती की चमकती सितारा

गुजरात से की शुरूआत, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी

पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में कार्यरत सामान्य सहायक श्री मनोज कुमार एवं श्रीमती अंजू देवी की सुपुत्री पूजा कुमारी ने कॉम्बैट कुश्ती में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। बिहार में जन्मीं पूजा वर्तमान में कर्नाटक से एमबीए की पढ़ाई कर रही हैं और उन्होंने अहमदाबाद (गुजरात) से अपने खेल करियर की शुरूआत की। कुश्ती का प्रशिक्षण उन्होंने पंजाब से प्राप्त किया।

पूजा ने अप्रैल 2024 में श्रीलंका में आयोजित एशियन चैंपियनशिप और मई 2024 में नेपाल में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का तिरंगा शान से लहराया। हाल ही में गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर लंदन में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

पूजा का कहना है, "मैट पर उतरने के बाद सिर्फ गोल्ड दिखता है, चाहे सामने कोई भी हो।" उनके इस सफर में परिवार, विशेषकर उनके पिता श्री मनोज कुमार और कोच मोनिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

गोरखपुर में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 400 से अधिक खिलाड़ियों की उपस्थिति में पूजा सहित कई प्रतिभागियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर खेलप्रेमियों ने कॉम्बैट कुश्ती को ओलंपिक में शामिल किए जाने की मांग भी दोहराई।

पूजा कुमारी की यह उपलब्धि न केवल रेलवे परिवार बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए गर्व का विषय है।

भाजपा युवा मोर्चा नेता का अश्लील वीडियो वायरल, जीत निशोदे को पद और सदस्यता से हटाया

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा युवा मोर्चा के अरेरा मंडल महामंत्री जीत निशोदे का एक महिला के साथ अश्लील वीडियो सामने आने से सियासी हलचल तेज हो गई है। यह वीडियो 9 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयानों को निशाने पर लिया।

बढ़ते हंगामे के बीच भाजपा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जीत निशोदे को युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया। इस घटना ने भाजपा की छवि पर सवाल उठाए हैं और शिक्षा क्षेत्र से लेकर राजनीति तक भ्रष्टाचार और नैतिकता के मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है। आइए, इस घटना और इसके बाद की प्रतिक्रियाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं।

वीडियो वायरल और भाजपा की कार्रवाई

बता दे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के अरेरा मंडल महामंत्री जीत निशोदे एक महिला के साथ अश्लील हरकतों में लिप्त नजर आए। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं।

हंगामा बढ़ता देख भाजपा युवा मोर्चा ने तुरंत कार्रवाई की। अरेरा मंडल अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित ने जीत निशोदे को मंडल महामंत्री के पद से हटाने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही, उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। पुरोहित ने एक बयान में कहा, "भाजपा में अनुशासन और नैतिकता सर्वोपरि है। इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जीत निशोदे को तत्काल प्रभाव से पद और सदस्यता से हटा दिया गया है।"

कांग्रेस का तीखा हमला: 'क्या यही है भाजपा का चरित्र?'

कांग्रेस ने इस घटना को भाजपा पर हमला करने का मौका बनाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "भाजपा परंपरा और संस्कारों की बात करती है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूसरी पार्टियों को चरित्र का सर्टिफिकेट बांटा था। अब वे बताएं कि क्या यही वह चरित्र है जिसका बखान वे करते हैं? क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को ऐसी अश्लील हरकतें सिखाती है?"

पटवारी ने आगे कहा, "जो लोग दूसरों के मकान पर पत्थर फेंकते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि उनका मकान कितने कमजोर शीशे का बना है। भाजपा के नेताओं के सेक्स स्कैंडल सड़क से लेकर सदन तक सामने आ रहे हैं। कभी नेता पोर्न देखते पकड़े जाते हैं, तो कभी पोर्न बनाने में लिप्त

भावनगर टर्मिनस -पोरबंदर दैनिक पैसेन्जर ट्रेन को खोडीयार मंदिर स्टेशन पर मिला अतिरिक्त ठहराव

यह ट्रेन 11 सितम्बर (गुरूवार) से खोडीयार मंदिर स्टेशन पर रूकना शुरू करेगी

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 59560/59557 भावनगर टर्मिनस -पोरबंदर दैनिक पैसेन्जर ट्रेन को खोडीयार मंदिर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है। यह सुविधा 11 सितम्बर, 2025 (गुरुवार) से प्रभावी होगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर मंडल श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार:-

- ट्रेन संख्या 59560 भावनगर टर्मिनस -पोरबंदर दैनिक पैसेन्जर भावनगर टर्मिनस से प्रतिदिन दोपहर 15:00 बजे प्रस्थान करती है और उसी दिन रात 22:10 बजे पोरबंदर पहुंचती है।
- इस ट्रेन का खोडीयार मंदिर स्टेशन पर आगमन समय 15:20 बजे तथा प्रस्थान समय 15:21 बजे होगा।
- वापसी में ट्रेन संख्या 59557 पोरबंदर -भावनगर टर्मिनस दैनिक पैसेन्जर प्रतिदिन पोरबंदर से सुबह 07:30 बजे प्रस्थान करती है और उसी दिन दोपहर 14:30 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचती है।
- इस ट्रेन का खोडीयार मंदिर स्टेशन पर आगमन समय 13:24 बजे तथा प्रस्थान समय 13:25 बजे होगा।

यात्रियों की सुविधा हेतु इस ट्रेन के ठहराव, संरचना एवं समयसारणी से संबंधित विस्तृत जानकारी भारतीय रेलवे की वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर उपलब्ध है।

कांग्रेस-आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव? सीट शेयरिंग से उम्मीदवारी तक, बैठक में सब होगा फाइनल

(जीएनएस)।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सियासत गरमा गई है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास आज (09 सितंबर) शाम अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कई वरिष्ठ नेताओं ने सीट शेयरिंग और संभावित उम्मीदवारों पर मंथन किया जा रहा है।

बैठक में सीट शेयरिंग से उम्मीदवारी तक पर बात की जाएगी। कांग्रेस, फ्खऊ, जेएमएम और अन्य सहयोगी पार्टियों को कितनी सीटें दी जानी है, इस बैठक में सब फाइनल होने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने साफ कहा कि सीटों पर चर्चा क्ठऊक्अ गठबंधन स्तर पर हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं से मार्गदर्शन लेकर ही रणनीति बनाएगी। वहीं, प्रभारी अल्लावरू ने दोहराया कि "हर साथी दल का सम्मान होना चाहिए और कांग्रेस इसी दिशा में काम करेगी।" 10 सितंबर को भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है।

कांग्रेस की मांग, 60-70 सीटें, फ्खऊ नहीं देना चाहती 50 से ज्यादा

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की मांग करीब 60 सीटों की है, जबकि आरजेडी उसे 50 सीटों पर सीमित रखना चाहती है। पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 जीती थीं, इसलिए इस बार दबाव बढ़ा है। वीआईपी, सीपीआई(एमएल) और अन्य सहयोगी दलों की बढ़ी मांग के चलते कांग्रेस के हिस्से में सीटें कम हो सकती हैं।

हाल ही में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस को नया आत्मविश्वास दिया था। यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए, लेकिन सारा क्रेडिट कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में गया। यही वजह है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही है।

गठबंधन सूत्रों का कहना है कि फ्खऊ लगभग 140 सीटों पर लड़ना चाहती है, वाम दल 30 से ज्यादा और वीआईपी 25 सीटें मांग रहे हैं। जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी को भी समायोजित किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस को फिलहाल 50 सीटें ही मिलती दिख रही हैं।

अब सबकी निगाहें 10 सितंबर पर टिकी हैं, जब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी करीब दो दर्जन संभावित उम्मीदवारों पर मुहर लगाएगी। बड़ा सवाल यही है-क्या आरजेडी झुकेगी और कांग्रेस को मनमाफिक सीटें मिलेंगी, या फिर महागठबंधन में अंदरूनी खींचतान तेज होगी?

महागठबंधन सीट शेयरिंग की संभावित तस्वीर

RJD को लगभग 136 सीटें मिल सकती हैं - जो कि उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी।

कांग्रेस को 52 सीटों की संभावना है।

वाम दल (CPI-ML, CPI, CPM) को मिल सकती हैं 31-33 सीटें

VIP (मुकेश सहनी) को 20-22 सीटें मिल सकती हैं

RLJP (पशुपति पारस) को 5-7 सीटें आवंटित की जा सकती हैं

JMM (हेमंत सोरेन) को 2-3 सीटें मिलने की उम्मीद है

सागर लोकायुक्त ने टीकमगढ़ में 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते दो आरोपियों को पकड़ा

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में लोकायुक्त पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 9 सितंबर 2025 को सागर लोकायुक्त इकाई ने टीकमगढ़ जिले के पलेरा तहसील में सीएम राइज स्कूल में 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक (लोकायुक्त) योगेश देशमुख के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पकड़े गए आरोपियों में एक सहायक शिक्षक और एक भृत्य शामिल हैं, जिन्होंने निलंबन अवधि के बकाया वेतन के भुगतान के लिए रिश्वत की माँग की थी। इस कार्रवाई ने शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर किया है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।

ट्रैप कार्रवाई: रंगे हाथों गिरफ्तारी

9 सितंबर 2025 को सागर लोकायुक्त इकाई ने सीएम राइज स्कूल, पलेरा में एक सुनियोजित ट्रैप ऑपरेशन के तहत 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त), सागर के नेतृत्व में निरीक्षक रंजीत सिंह और उनकी ट्रैप टीम द्वारा अंजाम दी गई। ट्रैप टीम में निरीक्षक कमल सिंह उईके और अन्य सदस्य शामिल थे।

घटना की पूरी कहानी

अनिल कुमार खरे, जो माध्यमिक विद्यालय बेला में सहायक शिक्षक हैं, को जनवरी 2023 में नए स्कूल में प्रभार न लेने के कारण निलंबित किया गया था। जुलाई 2023 में उनकी बहाली हुई, लेकिन उनकी निलंबन अवधि का बकाया वेतन (लगभग 2.5 लाख रुपये) उनके खाते में जमा नहीं हुआ। इस बकाया वेतन को जल्दी ट्रांसफर करवाने के लिए कैलाश कुमार खरे (सहायक शिक्षक, सीएम राइज स्कूल) और शंकरलाल कटारे (भृत्य, माध्यमिक विद्यालय टोरिया) ने 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की।

अनिल कुमार खरे ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए लोकायुक्त कार्यालय, सागर में शिकायत दर्ज की। पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त), सागर ने निरीक्षक रंजीत सिंह को शिकायत के सत्यापन का आदेश दिया। सत्यापन के दौरान आरोपियों ने रिश्वत की राशि को 2 लाख रुपये तक कम किया और अंततः 1 लाख रुपये लेने पर सहमत हुए।

9 सितंबर 2025 को सीएम राइज स्कूल, पलेरा में लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही अनिल कुमार खरे ने 1 लाख रुपये की रिश्वत आरोपियों को दी, निरीक्षक रंजीत सिंह और उनकी टीम ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त), सागर ने बताया, "आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(f) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनकी संपत्तियों और बैंक खातों की जाँच शुरू हो चुकी है।"

'एकता राहुल गांधी जी की खत्म?', उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन की जीत पर निशिकांत दुबे का आया बड़ा बयान

(जीएनएस)।

देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने शानदार जीत दर्ज की है। मंगलवार, 9 सितंबर 2025 को घोषित हुए नतीजों के बाद उन्हें कुल 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोटों से संतोष करना पड़ा। इस परिणाम के साथ ही सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह "नक्सलवादी सोच की हार" है।

विपक्ष टुकड़ों-टुकड़ों में बंट गया

निशिकांत दुबे ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष "टुकड़ों-टुकड़ों में बंट गया" है। दुबे ने यह भी दावा किया कि एनडीए उम्मीदवार को विपक्ष के 15 वोट मिले, जबकि 15 विपक्षी सदस्यों ने अपने वोट बर्बाद कर दिए। उन्होंने प्रश्न किया, "एकता राहुल गांधी जी की खत्म हुई?"

उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 वोट रद्द कर दिए गए?

उपराष्ट्रपति चुनाव के कुल आंकड़ों के अनुसार, कुल 767 वोट पड़े, जिनमें से 752 वैध पाए गए और 15 वोट रद्द कर दिए गए। लोकसभा और राज्यसभा में कुल 788 सांसद हैं, जिनमें से सात सीटें रिक्त थीं, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या 781 थी। बीजू जनता दल (बीजेडी), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और शिरोमणि अकाबि अकाली दल जैसे कुछ दलों ने इस चुनाव से दूर रहने का निर्णय लिया था।

कौन से भागकर हमको यानि NDA प्रत्याशी को वोट दे दिए?

एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा, "मिले तो 300 ही, 15 लोग कौन से भागकर हमको यानि ठऊअ प्रत्याशी को वोट दे दिए? भाई आपके तो जनता के साथ नेता भी भाग गए।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से नहीं, बल्कि मतपत्रों (बैलेट पेपर) के माध्यम से संपन्न हुआ।

फ्रीड्ढेल्लाीि त्रक्ष्१ ड्ड४

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्ठऊक्अ गठबंधन को लगा तगड़ा झटका, जमकर हुई क्रॉस वोटिंग, ठऊअ को मिले उम्मीद से अधिक वोट

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्ठऊक्अ गठबंधन को लगा तगड़ा झटका, जमकर हुई क्रॉस वोटिंग, ठऊअ को मिले उम्मीद से अधिक वोट

गौरतलब है कि मतदान प्रक्रिया मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे समाप्त हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित 760 से अधिक सांसदों ने इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

संकर्षण ठाकुर: भारतीय पत्रकारिता का निर्भीक, सटीक और सरल हस्ताक्षर, बिहार से विश्व तक रहेगी जिसकी अमिट छाप

(जीएनएस)।

ले बलैय्या...! संकर्षण ठाकुर नहीं रहे। "ले बलैय्या..." मैथिली की आम बोलचाल में कहा जाने वाले इस विस्मयादिबोधक पद को वर्षों तक अपना व्हाट्सऐप स्टेटस बनाकर रखने वाले देश के शीर्षस्थ पत्रकारों में से एक संकर्षण ठाकुर के निधन पर शोक के साथ यह स्टेटस याद हो आया। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति विदा होने के बाद भी लंबे समय तक महसूस होती रहती है। संकर्षण ठाकुर उन्हीं में से एक थे। एक ऐसे पत्रकार, जिनकी कलम ने न केवल अपने समय की सियासत को नए कोण से समझाया बल्कि आने वाले समय की आहटें भी बेहद सटीकता से पकड़ीं, अब हमारे बीच नहीं हैं।

जीवन के अंतिम समय तक द टेलीग्राफ समूह के एडिटर इन चीफ रहे ठाकुर पत्रकारिता में अमूल्य ख्याति छोड़कर वे इस संसार से कूच कर चुके हैं। तेज चमक-दमक वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उफान के दौर में भी वे हमेशा प्रिंट मीडिया की गंभीरता को चुना। वो कहते थे कि खबरें सतही नहीं, गहरी होनी चाहिए, और पत्रकार को शोर नहीं, असर छोड़ना चाहिए। आज पत्रकारिता का वो इंस्टीच्युशन इस विधा पर अपना गहरा असर छोड़कर जा चुका है।

रंल्ल'१रॅल्ल ळॅं४१ ळ्री'ल्ली

पत्रकारिता में सर्वोपरी नैतिकता

संकर्षण ठाकुर का नैतिक बल अदम्य था। व्यवसायिकता के इस दौर में भी उन्होने पत्रकार की गरिमा और नैतिकता को सर्वोपरी रखा। 2015 के बिहार चुनाव कवरेज के दौरान का एक वाकया है। देश के इतने बडे पत्रकार को मैदान में देख कई पार्टिया ँ लॉजिस्टिक्स सुविधा उपलब्ध करवाना चाहती थी। संकर्षण ठाकुर अपने जुनियर्स को प्यार से समझाते थे, "आज किसी नेता की गाड़ी पर चढोगे तो कल वो माथे पर चढ जाएगा।

उनका यही नैतिक बल था कि किसी भी राजनीतिक शक्ति के सामने उन्होंने अपनी कलम को झुकने नहीं दिया। 90 के दशक से लेकर 2000 के शुरूआती वर्षों में बिहार की सत्ता में लालू प्रसाद यादव वर्चस्व और निरंतर हो रहे अपराध ने माननीय न्यायालय को भी "जंगलराज" कहने पर मजबूर कर दिया था। उस दौर में जहा ँ लोग ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलने से भी डरते थे, संकर्षण ठाकुर ने उन्हीं दिनों बिहार में अराजकता पर बोल्ड किताब लिख दिया - " सबल्टन साहेब: बिहार एंड दी मेकिंग ऑफ लालू यादव"। इतनी निर्भीकता उच्च नैतिकता, ईमानदारी और जवाबदेही से ही आती है।

राजनीतिक पत्रकारिता और अचूक अनुमान

भारत की राजनीति को तुरंत पढ़ लेना और उसके संकेतों को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में समझना संकर्षण ठाकुर की सबसे खास क्षमता थी। उनकी लेखनी में न तो विचारधारा की अंधभक्ति थी, न ही नेताओं की चापलूसी। वे सत्ताधारी नेताओं के लिए असुविधाजनक और विरोधियों के लिए असहज करने वाले सवाल पूछते थे।

उनका सबसे चर्चित योगदान यह रहा कि वे पहले पत्रकार थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया था। यह 2002 के आसपास की बात है, जब गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय विमर्श में विवाद के केंद्र थे। उस समय अधिकांश पत्रकार उनकी राजनीतिक संभावनाओं को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन संकर्षण ठाकुर ने लिखा कि मोदी की राजनीति केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहेगी। लगभग बारह साल बाद उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई।

इसी तरह 2014 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी आई, तो संकर्षण ठाकुर ने दो टूक कहा कि भाजपा किसी भी हालत में बिहार चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाएगी। उस समय पूरे देश के विश्लेषक और सर्वेक्षण यह बता रहे थे कि मोदी लहर बिहार को भी बहा ले जाएगी। लेकिन ठाकुर डटे रहे। 2015 में चुनाव परिणाम आने पर उनकी भविष्यवाणी अक्षरशः सही साबित हुई। भाजपा उतनी ही सीटों पर सिमट गई जितनी कि उन्होंने अनुमान लगाई थी। पत्रकारिता में इस तरह की दूरदर्शिता बहुत कम देखने को मिलती है।

देश की राजनीति की नब्ज पहचानने वाले ठाकुर जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक मामलों पर भी अत्यंत पैनी नजर रखते थे। कश्मीर की राजनीतिक समस्या की परख और विश्लेषण में उन्हे महारत हासिल थी। वर्ष 2003 में कश्मीर पर रिसर्च के लिए उन्हें अप्पन मेनन फेलोशिप दिया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001 में राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए उन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार से नवाजा गया था।

ठाकुर की लेखन-शैली

संकर्षण ठाकुर के लेख केवल खबर भर नहीं होते थे। वे शब्दों से एक दृश्य खड़ा करते थे। राजनीति की भीतरी चालों, नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और जनता की उम्मीदों को वे ऐसे पिरोते कि पाठक को लगता जैसे आंखों के सामने एक पूरा नाटक चल रहा हो।

एशिया कप 2025: 'शर्मनाक हरकत', भारत को धमकी देने वाले मोहसिन नकवी से एसकेवाई ने मिलाया हाथ, हुए ट्रोल

(जीएनएस)।

एशिया कप 2025 (अ२ं उ४स्र 2025) शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव सोशल मीडिया पर फैंस के निशाने पर आ गए हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी से एक मुलाकात सूर्यकुमार यादव पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

मोहसिन नकवी ने सूर्या ने मिलाया हाथ

इन दोनों का हाथ मिलाने वाला वीडियो जैसे ही सामने आया, भारतीय फैंस का बड़ा वर्ग नाराजगी जताने लगा और कप्तान को ट्रोल करने लगा। दरअसल, मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और हाल ही में भारत विरोधी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा है। ऐसे माहौल में सूर्यकुमार का उनसे हाथ मिलाना कई भारतीयों को नागवार गुजरा।

बीसीसीआई पर भी उठे सवाल

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि जब सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तब क्रिकेट कप्तान को इतनी सहजता से दुश्मन देश के नेता से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। कई लोगों ने इसे शर्मनाक हरकत बताते हुए बीसीसीआई पर भी सवाल खड़े किए। एक यूजर ने लिखा कि ये तस्वीर सबसे घटिया है, हमारे खिलाड़ियों को थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

कुछ फैंस ने किया सपोर्ट

वहीं, कुछ ने कहा कि मोहसिन नकवी वही शख्स हैं जिन्होंने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी, ऐसे में उनसे हाथ मिलाना सही संदेश नहीं देता। हालांकि, कुछ लोगों ने इस पल को खेल भावना से जोड़कर देखा। उनका कहना है कि क्रिकेट सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि आपसी सम्मान और एकता का प्रतीक है। एक यूजर ने लिखा कि ये हैंडशेक दिखाता है कि खेल रिश्ते बिगाड़ने नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ऑल गुजरात कैटरर्स एसोसिएशन एक्सपो का उद्घाटन किया

9 और 10 सितंबर को आयोजित इस एक्सपो में 150 स्टॉल और लगभग 2500 एग्जीबिटर्स ले रहे हैं हिस्सा

गांधीनगर, 09 सितंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को अहमदाबाद में ऑल गुजरात कैटरर्स एसोसिएशन (एजीसीए) एक्सपो-2025 का उद्घाटन किया।

इस एक्सपो में 150 स्टॉल और लगभग 2500 एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। 9 और 10 सितंबर को आयोजित इस दो दिवसीय एक्सपो में विभिन्न देशों के व्यंजनों के साथ-साथ पाक कला का प्रदर्शन किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न कैटरर्स स्टॉल का अवलोकन कर कैटरर्स एसोसिएशन के अग्रणियों

से कहा कि राज्य सरकार ह्यमेदस्विता मुक्त गुजरातह्न (मोटापा मुक्त गुजरात) अभियान चला रही है, तब हमें भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और कैटरर्स द्वारा बनाए जाने वाले व्यंजनों में तेल की मात्रा को कम कर लोगों के स्वास्थ्य सुधार के काम में सहभागी बनना चाहिए।

खाद्य, पाक कला और पेय पदार्थों के 150 से अधिक स्टॉल में कैटरर्स के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन इस कैटरिंग एक्सपो का विशेष आकर्षण है। इसके अलावा, कैटरिंग एसोसिएशन के सदस्यों को विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन देने के लिए वर्कशॉप और सेमिनारों का आयोजन भी किया गया है।

कैटरिंग एसोसिएशन के सदस्यों और प्रतिनिधियों के साथ ज्ञान एवं अनुभव के आदान-प्रदान का एक बेहतरीन मंच प्रदान करने वाले इस एक्सपो में खाद्य एवं पेय उद्योगों से जुड़े देश भर के लगभग 5000 से अधिक लोग शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दृष्टिवान नेतृत्व में राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा अर्निंग वेल-लिविंग वेल मंत्र को पूरा करने वाला 'गुजरात जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025' विधानसभा में पारित हुआ

गांधीनगर, 09 सितंबर :धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिवान नेतृत्व में विकसित भारत@2047 के लिए विकसित गुजरात के निर्माण की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तथा पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस के चलते गुजरात आज जब विश्वभर के निवेशकों की पहली पसंद बना है, तब ह्यईज ऑफ डूइंग बिजनेसह्न को वेग देकर अर्निंग वेल-लिविंग वेल की संकल्पना साकार करने का राज्य सरकार का ध्येय है।

15वीं गुजरात विधानसभा के सातवें सत्र के दूसरे दिन उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदन में ह्यगुजरात जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025ह्न प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के सरलता एवं पारदर्शिता की ओर एक और ठोस कदम के रूप में पारित हुआ यह जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025 राज्य में कानून के पालन को आसान बनाकर, डिजिटलाइज्ड कर तथा सुयोग्य ढंग से बदलाव लाकर व्यापार सरलता के साथ जीवन जीने की सरलता में भी वृद्धि करने वाला सिद्ध होगा। इतना ही नहीं; न्यायपालिका पर बोझ घटाने में भी यह विधेयक उपयुक्त बनेगा।

मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत ने सदन में इस जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025 की पृष्ठभूमि रखते हुए कहा कि किसी भी देश में विकास के लिए स्थिर नीतियाँ तथा अच्छा व्यावसायिक माहौल बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने हमेशा कानूनों को आधुनिक, फ्लेक्सिबल, पीपल फ्रेंड्ली तथा विश्वास आधारित बनाया है। सरकार ने आम नागरिकों तथा उद्योगों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है।

इतना ही नहीं; टेक्नोलॉजी के उपयोग से त्वरित एवं अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्रों में उनके मार्गदर्शन का भी सरकार ने स्वागत किया है। इसलिए केन्द्र सरकार ने 2023 में जनविश्वास अधिनियम लागू कर कम्प्लायंसेज घटाने का प्रयास किया है। इस दिशा में केन्द्र व राज्य स्तर पर 40 हजार से अधिक कम्प्लायंसेज निर्मूल किए गए। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिला है। हाल ही में संसद में जनविश्वास विधेयक 2.0 प्रस्तुत हुआ है।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के जनविश्वास विधेयक 2.0 का विस्तृत अध्ययन करने के बाद गुजरात जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025 तैयार किया है।

आईईपीएफए ने 'अदावाकृत का दावाः भारत में निष्क्रिय वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षमता को उजागर करना' विषय पर गोलमेज सम्मेलन के साथ 9वां स्थापना दिवस मनाया

इस सत्र में वरिष्ठ नीति निमार्ताओं, नियामकों और विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भागीदारी की

(जीएनएस)।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने 08 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में एक गोलमेज सम्मेलन के साथ अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। सम्मेलन का विषय "अदावाकृत का दावाः भारत में निष्क्रिय वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षमता को उजागर करना" था।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्री संजीव सान्याल ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अपना संबोधन दिया। श्री संजीव सान्याल ने नवीन नीतिगत ढांचों और अंतर-एजेंसी समन्वय की अत्यंत आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निष्क्रिय वित्तीय परिसंपत्तियों का राष्ट्रीय विकास के लिए उत्पादक उपयोग किया जा सके। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुधारों के लिए आईईपीएफए द्वारा की गई पहलों की सराहना की।

आईईपीएफए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री अनीता शाह अकेला ने अपने उद्घाटन संबोधन में निवेशक संरक्षण को मजबूत करने, दावा निपटान को सरल बनाने और पूरे भारत में वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए आईईपीएफए की पहलों का उल्लेख किया।

एनसीएईआर के आईईपीएफ चेयर प्रोफेसर डॉ. सीएस महापात्रा ने गोलमेज सम्मेलन का संचालन करते हुए दावा समय-सीमा को कम करने, पारदर्शिता में सुधार करने और निवेशकों का अधिक विश्वास बनाने के लिए सहयोगात्मक सुधारों के महत्व को रेखांकित किया।

सत्रों में वरिष्ठ नीति निमार्ताओं, नियामकों और विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। पूंजी बाजार और बैंकिंग क्षेत्र से, चचाओं में श्री सुनील कदम, कार्यकारी निदेशक, सेबी; श्री सुनील नायर, मुख्य महाप्रबंधक, आरबीआई और सीएस बी नरसिम्हन, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई शामिल थे। बीमा, पेंशन और भविष्य निधि का प्रतिनिधित्व सुश्री सुमीत कौर कपूर, कार्यकारी निदेशक, पीएफआरडीए और श्री आर.के. नायर, पूर्व सदस्य, आईआरडीएआई थे। प्रतिमान बदलाव निष्क्रिय संपत्तियों और कुशल सेवा की क्षमता को अनलॉक करना सत्र में श्री धीरेंद्र कुमार, बोर्ड सदस्य, आईईपीएफए और सीईओ, वैल्यू रिसर्च; श्री शशि कृष्णन, निदेशक, एनआईएसएम और सुश्री सावित्री पारेख, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अंतर्दृष्टि शामिल थी।

गोलमेज सम्मेलन का समापन सभी हितधारकों की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हुआ, जिसमें दावा न की गई परिसंपत्तियों की क्षमता को उजागर करने, वित्तीय समावेशन को मजबूत करने तथा भारतीय वित्तीय इकोसिस्टम में निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ करने की बात कही गई।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने सहकारी आधारित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने आज एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारत के सहकारी आधारित कृषि निर्यात को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाना है। यह समझौता ज्ञापन सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी की उपस्थिति में संपन्न हुआ जो सहकारिता मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की शक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस टङ्कव पर अढएऊअ की ओर से अध्यक्ष, श्री अभिषेक देव और ठउएछ की ओर से प्रबंध निदेशक, श्री अनुपोम कौशिक ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि NCEL के नेटवर्क को अढएऊअ की निर्यात सुविधा से जोड़ने से किसानों को बेहतर मूल्य

प्राप्त होगा, ग्रामीण आजीविकाओं को मजबूती मिलेगी और यह नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के उद्देश्यों के अनुरूप भारत की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और सुदृढ़ करेगी ।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय, सहकारी संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के विजन पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि NCEL और APEDA संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, निर्यात हेतु गुणवत्ता मानकीकरण, अवसंरचना सहयोग एवं पुनर्जीवन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और बाजार में स्थिति निर्माण, मार्केट इंटेलिजेंस एवं डेटा विश्लेषण तथा वस्तु-विशेष निर्यात रणनीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

डॉ. भूटानी ने कहा कि सहकारी समितियों को इस टङ्कव के अंतर्गत संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से वैश्विक गुणवत्ता मानकों, खाद्य सुरक्षा और निर्यात डोक्युमेंटेशन की समझ विकसित होगी। उन्होंने कहा कि अढएऊअ की निर्यात सुविधा को ठउएछ के व्यापक नेटवर्क से जोड़कर फलों, सब्जियों, मसालों, प्रसंस्कृत खाद्य, अनाज और पशु उत्पादों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को और सुगम बनाया जा सकता है।

आत्मनिर्भर भारतः आईडीईएक्स-डीआईओ और एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड ने नए एस्पायर कार्यक्रम के तहत दोहरे उपयोग वाली तकनीक विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार - रक्षा नवाचार संगठन (आईडीईएक्स-डीआईओ) ने दोहरे उपयोग वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नए एस्पायर (अनुसंधान और शिक्षा में रणनीतिक प्रगति में तेजी) कार्यक्रम द्वारा संचालित, रक्षा विशेषज्ञता को उभरते एड-टेक समाधानों से जोड़ता है। आईडीईएक्स-डीआईओ रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। वहीं, एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड शिक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी-क केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है।

इस समझौता ज्ञापन पर संयुक्त सचिव (डीआईपी) एवं अतिरिक्त सीईओ, डीआईओ श्री अमित सतीजा और संयुक्त सचिव (टीईएल), शिक्षा मंत्रालय एवं सीएमडी, एडसिल श्री

गोविंद जायसवाल ने 9 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य आईडीईएक्स के नवाचार मॉडल को नागरिक क्षेत्र तक विस्तारित करना, महत्वपूर्ण चुनौतियों को लक्षित करना और दोनों संगठनों की क्षमताओं एवं विशेषज्ञता का लाभ उठाकर ऐसी नवीन तकनीकों को बढ़ावा देना है जो स्वदेशी क्षमताओं पर भारत के बढ़ते जोर को दर्शाती हैं। यह सहयोग देश के स्टार्ट-अप इको-सिस्टम का प्रभावी ढंग से उपयोग करके स्केलेबल और प्रभावशाली नवाचारों को विकसित करने में एक नया अध्याय शुरू करता है।

आईडीईएक्स के बारे में

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू किया गया, आईडीईएक्स रक्षा इको-सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में उभरा है। बहुत कम समय में इसने गति पकड़ी है और इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स के बढ़ते समुदाय को बढ़ावा दिया है। यह वर्तमान में 650 से अधिक स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई के साथ जुड़ा हुआ है। अब तक, नोडल एजेंसियों से 50 उत्पादों के लिए 3,250 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। साथ ही आईडीईएक्स ढांचे के तहत विकसित 36 उत्पादों के लिए 1,652 करोड़ रुपये के खरीद आदेश दिए जा चुके हैं।

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री 10 सितंबर को अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करेंगे

(जीएनएस)।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के भारत के मिशन के अनुरूप 10 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कोलकाता की अलीपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करेंगे।

उन्नत बुनियादी ढांचे से सुसज्जित, यह प्रयोगशाला ईवी बैटरियों और उनके पुर्जों पर महत्वपूर्ण परीक्षण करेगी, जिनमें विद्युत सुरक्षा, एफसीसी/आईएसईडी अनुपालन, कार्यात्मक सुरक्षा, स्थायित्व, जलवायु परीक्षण (आईपी, यूवी, संक्षारण), और यांत्रिक एवं भौतिक सुरक्षा (ज्वलनशीलता, ग्लो वायर, आदि) शामिल हैं। यह सुविधा विशेष रूप से पूर्वी भारत में ईवी बैटरी निमार्ताओं को विश्वसनीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परीक्षण और प्रमाणन प्रदान करेगी, जिससे उत्पाद सुरक्षा, प्रदर्शन और नियामक अनुपालन सुनिश्चित होगा।

यह सुविधा इलेक्ट्रिक वाहनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मानक के रूप में कार्य करेगी, जिससे निमार्ताओं को शीघ्र त्रुटि पहचान, उत्पाद विश्वसनीयता में वृद्धि और कड़े सुरक्षा एवं प्रदर्शन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं में आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और भारत की हरित गतिशीलता की यात्रा में तेजी आएगी।

इस सुविधा की स्थापना एक सशक्त ईवी इकोसिस्टम बनाने, आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू निमार्ताओं को किफायती परीक्षण सेवाओं के साथ दृढ़ बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस विकास के साथ, एनटीएच भारत के सतत परिवहन में एक प्रमुख प्रवर्तक और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करता है।

इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण-अनुकूल गतिशीलता समाधानों की ओर वैश्विक बदलाव में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ उत्सर्जन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत ने 2030 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच (30@30) हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इलेक्ट्रिक वाहन और उनके घटक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कठोर परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन से तैयार हो।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना एसपीआरईई-2025 और विवाद समाधान संबंधी एमनेस्टी योजना से सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा

नियोक्ताओं को सरल पंजीकरण की सुविधा और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा - ईएसआईसी निदेशक (प्रभारी), गुरुग्राम

(जीएनएस)।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने उद्योगों के लिए सामाजिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ और अनुपालन सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दो प्रमुख पहल - एसपीआरईई-2025 और एमनेस्टी योजना-2025 आरंभ की है। ईएसआईसी उप-क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के प्रभारी निदेशक श्री सुनील यादव ने आज गुरुग्राम के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाना है और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत प्रदान करना है।

नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना - एसपीआरईई-2025 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत जो उद्योग और कर्मचारी अभी तक ईएसआईसी से संबद्ध नहीं हैं, वे पुराने बकाये की मांग के बिना ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के

पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। एसपीआरईई-2025 के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से ही इसके अंतर्गत माना जाएगा और नए पंजीकृत कर्मचारियों को पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। श्री यादव ने जोर देकर कहा कि इस योजना में दंडात्मक उपायों की बजाय स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी में कमी लाना, औपचारिक पंजीकरण को प्रोत्साहित करना और नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के बीच आपसी विश्वास एवं सहयोग का माहौल निर्मित करना है।

श्री यादव ने अन्य सुधार एमनेस्टी योजना-2025 की घोषणा की, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। यह एकमुश्त विवाद समाधान पहल है, जो हजार्ने, ब्याज और ईएसआई अधिनियम के तहत आने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार की गई है। इस योजना का मकसद नियोक्ताओं को लंबित विवादों को सुलझाने और अनुपालन में सुधार के अवसर प्रदान करना है, जिससे मुकदमों की संख्या में कमी आएगी और कर्मचारियों को सुचारू रूप से सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित होंगे।

विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इन योजनाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इनसे छोटे और बड़े, दोनों प्रकार के उद्योगों को काफी राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ अधिक सुगमता से मिलेंगे। संवाददाता सम्मेलन में वरिष्ठ अधिकारियों में उप निदेशक श्री सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक श्री कमलेंद्र कुमार, और ईएसआईसी उप-क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।

ये पहल सामाजिक सुरक्षा दायरे में विस्तार, नियम-अनुपालन में सुगमता बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी रूस में बहुपक्षीय अभ्यास जेडएपीएडी 2025 के लिए रवाना हुई

(जीएनएस)।

भारतीय सशस्त्र बलों का 65 कार्मिकों वाला एक दल आज बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापाड 2025 (जेडएपीएडी2025) में भाग लेने के लिए मुलिनो प्रशिक्षण मैदान, निजनी, रूस के लिए रवाना हुआ। यह अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

इस सैन्य टुकड़ी में भारतीय सेना के 57 जवान, भारतीय वायु सेना के 7 जवान और भारतीय नौसेना का 1 जवान शामिल है। भारतीय सेना की इस टुकड़ी का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन और अन्य सेनाओं के जवान कर रहे हैं। बहुपक्षीय अभ्यास जापाड 2025 का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, अंतर-संचालन में सुधार करना तथा भाग लेने वाली सेनाओं को पारंपरिक युद्ध और आतंकवाद-रोधी अभियानों के क्षेत्र में रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह अभ्यास खुले और समतल भूभाग में संयुक्त कंपनी स्तर के अभियानों पर केंद्रित होगा। यहां सैनिक संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास और विशेष शस्त्र कौशल जैसे विभिन्न अभियानों को अंजाम देंगे। यह संयुक्त परिचालन क्षमताओं को निखारने, उभरती तकनीकों को एकीकृत करने और बहुराष्ट्रीय युद्ध वातावरण में संचालन करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा।

अभ्यास जापाड 2025 में भागीदारी से रक्षा सहयोग और मजबूत होगा तथा भारत और रूस के बीच सौहार्द बढ़ेगा। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास की भावना मजबूत होगी।

उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के अंतर्गत जैव-उत्तेजक उत्पादों का विनियमन

(जीएनएस)।

उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 में जैव-उत्तेजक उत्पादों को शामिल किए जाने से पहले, बाजार में लगभग 30,000 उत्पाद उपलब्ध थे। देश में जैव-उत्तेजकों को विनियमित करने के लिए, भारत सरकार ने 23 फरवरी, 2021 को अधिसूचना संख्या एस.ओ. 882 (ई) जारी की, जिसके द्वारा जैव-उत्तेजकों को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 में शामिल किया गया है और जैव-उत्तेजकों की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए खंड 20सी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ) के अनुसार, "जैव-उत्तेजक" का अर्थ है एक पदार्थ या सूक्ष्म जीव या दोनों का संयोजन जिसका प्राथमिक कार्य पौधों, बीजों या राइजोस्फीयर पर लागू होने पर पौधों में शारीरिक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करना और पोषक तत्वों की मात्रा की परवाह किए बिना इसके पोषक तत्वों के अवशोषण, वृद्धि, उपज, पोषण दक्षता, फसल की गुणवत्ता और तनाव के प्रति सहनशीलता को बढ़ाना है।